

**Water mains in Vishwas Nagar,
Shahadara**

4006. KUMARI KAMLA KUMARI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2952 dated 12th March, 1980 and state:

(a) whether Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking was to lay the water mains in block Nos. 31, 32, 33 Vishwas Nagar, Shahadara, Delhi-32 as per resolution No. 379 dated 14th February, 1979 but the said scheme dated 5th March, 1974 was not implemented;

(b) whether Government are also aware of the fact that 87 agreement forms submitted in year 1973-75 by the people have not been passed by the authorities if so, whether Government propose to take up the matter; and

(c) whether Government propose to ask the authorities to implement the scheme at top priority basis and also take action against the defaulting officials?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi has informed as under:—

(a) The scheme dated 5-3-74 could not be implemented as the residents/plot-holders did not fulfil the requisite conditions.

(b) According to the policy of the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking then in force, the work was to be taken in hand after 40 per cent of the total number of plot-holders/residents or 100 plot-holders/residents had executed agreements to pay development charges. Out of the total of 328 plots, only 47 plot-holders signed agreement upto 5-9-74 when this policy was discontinued. 37 agreements (40 as claimed by the residents) were deposited by the plot-holders/residents in March,

1975 but the same were not accepted as the policy had been discontinued on 5-9-1974. Even if these agreements are taken into account the original condition of 100 agreements or 40 per cent of the total number of agreements is not satisfied.

(c) The scheme can be implemented by the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking only when the plot-holders satisfy the conditions prescribed by the Undertaking for taking up development works in unauthorised colonies.

मनुष्यों तथा जानवरों के लिए पीने का पानी

4007. श्री कुम्भा राम शर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार ऐसे गांवों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जहां कुम्भों में जहरीला पानी होता है और जिसे पीकर मनुष्यों तथा जानवरों की मृत्यु हो जाती है ; और

(ख) ऐसे गांवों के लोगों तथा उनके जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) तथा (ख) पेयजल की व्यवस्था की अग्रता के लिए ग्रामों का वर्गीकरण निम्नलिखित मान दंड पर किया जाता है अर्थात् वह ग्राम जहां जल का स्रोत 1.6 कि० मी० की दूरी पर या 15 मीटर की गहराई पर हो या जिन ग्रामों में जल के स्रोत में बीमारी के किटाणु हों या जहां जल के स्रोतों में स्वास्थ्य के लिए हानिकर अत्याधिक खनिज पदार्थ हों ।

1972 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे ज्ञात हुआ कि 1.53 लाख ऐसे गांव हैं जो उपर्युक्त कसौटी की पूर्ति करते हैं । इन ग्रामों को समस्या-ग्रस्त ग्राम नामित किया गया है ।

तथापि, राज्य सरकारों ने बतलाया है कि सर्वेक्षण अपूर्ण था और यह कि और अधिक ग्राम समस्या-ग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में आते हैं । राज्यों को ऐसे ग्रामों की अन्तिम सूची को बनाने को कहा गया है । यह अनुमान लगाया गया है कि उनकी संख्या लगभग 2 लाख होगी । यह विचार किया गया है कि (1980-85) के दौरान शेष ग्रामों में राज्य क्षेत्र की संशोधित न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम में किए जाने वाले

संसाधनों तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम में दी जाने वाली निधियों द्वारा पेय जल की व्यवस्था कर दी जायेगी।

केन्द्रीय लोक सेवा निर्माण विभाग (उद्यान विभाग) में उप-निदेशकों के स्वीकृत पदों की भर्रा जाना

4008. श्री राम स्वरूप राम : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार लोक सेवा निर्माण विभाग (उद्यान विभाग) में नवम्बर, 1979 में उप-निदेशकों के दो पदों को स्वीकृत किया गया था;

(ख) क्या सितम्बर, 1979 में स्वीकृत किए गए एक पद को स्वीकृति के तुरन्त बाद ही तदर्थ रूप से भर दिया गया था जबकि उपरोक्त पदों की सात माह से अधिक समय बीत जाने पर भी रिक्त रखा जा रहा है ; और

(ग) यदि हा, तो इस के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) उप-निदेशक उद्यान का एक पद अक्टूबर, 1979 में बनाया गया था। दूसरा पद नवम्बर, 1979 में एक उप-निदेशक उद्यान की पदोन्नति से रिक्त हुआ।

(ख) तथा (ग). एक पदाधिकारी के एक वर्ष की छुट्टी पर जाने से अगस्त 1979 में एक इस ग्रेड में एक अत्यावधि रिक्त हुई। इसकी सितम्बर 1979 में तदर्थ आधार पर भरा गया था। इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति में कतिपय कठिनाइयों के कारण ही नियमित रिक्तियों को अभी तक नहीं भरा गया है।

Loss due to idle Aircraft with H.A.L.

4009. SHRI CHHITUBHAI GAMIT: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether some 60 Basant aircraft are lying with H.A.L. without being taken delivery of by Agriculture Ministry;

(b) if so, the grounds on which the Ministry has cancelled the earlier order;

(c) the amount to be spent in this purchase and amount of loss due to cancellation; and

(d) what the Government propose to do with these idle aircraft?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): (a) No, Sir. The number of aircraft is only 8.

(b) Even though H.A.L. was informed in October, 1972 by the Ministry of Agriculture that they had decided to place an order of 100 aircraft (Basant) with an option of another 100, in the agreement executed between the Ministry of Agriculture and H.A.L. in August, 1976, it was, however, indicated that HAL would supply only 34 Nos. Basant aircraft to the Directorate of Agriculture Aviation including these already delivered.

Main reasons for executing an agreement for delivery of only 34 Nos. of Basant aircraft were—

(i) Inadequate work arising for Fixed Wing aircraft and subsequent under-utilizing of the existing fleet; and

(ii) Absence of demand from the State Governments, Public and Private Sector Undertakings for Basant Aircraft.

(c) and (d). The cost of 8 Nos. Basant Aircraft is expected to be around Rs. 60 lakhs. Since the purchase of these aircraft is under consideration of the Government, the question of loss due to cancellation does not arise.

नालन्दा, बिहार में झालू उत्पादन

4010. श्री विजय कुमार यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नालन्दा जिला देश के सब से अधिक झालू उत्पादक केन्द्रों में एक बड़ा केन्द्र है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में झालू का उत्पादन उसकी खपत से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप झालू उत्पादकों को अपनी उत्पादन